cal care facilities for treatment of tobacco related diseases, losses due to fire hazard, ecological damage due to deforestation and disposal of tobacco related waste on the other hand with a view to making an economic study of the impact of tobacco consumption.

राज्य व्यापार निगम का गैर सरकारीकरण

1111. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम की कार्यशैली और उसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने और उसमें आवश्यक परिवर्तन करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम आयातकों/निर्यातकों पर कठोर शर्तें लगा रहा है जिसके परिणामस्वरूप वहां पर बड़े पैमाने पर कदाचार और नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त निगम के निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया है; और

(च) राज्य व्यापार निगम और वाणिज्य संबंधी संसदीय अस्थाई समिति के बीच हुई बैठकों का क्या परिणाम रहा है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) और (ख) एस०टी०सी० के जरिए अब तक किए जा रहे अनेक मदों के आयात और निर्यात के सरणीयन को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप सरकार उदारीकृत अर्थ व्यवस्था और प्रतिस्पर्धी वातावरण के अनुकूल एस०टी०सी० को पुनः पूर्व-स्थिति में लाने की जरूरत की समीक्षा करती रही है। अपने व्यापार क्रिया-कलापों के विस्तार के एक भाग के रूप में खासकर गैर-सरणीकृत क्षेत्र में, एस०टी०सी० द्वारा निम्नलिखित कार्य-योजनाओं को अपनाकर प्रमुख कार्यक्रमों का विविधिकरण किया जा रहा है:—

—प्रत्यक्ष खरीद एवं बिक्री पर अधिक बल देकर;

—विदेशी विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर;

—संयुक्त उद्यमों में प्रवेश के जरिए;

—ओ०जी०एल० आयात करके;

—घरेलू व्यापार का विस्तार करके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एस०टी०सी० ने वाणिज्य मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और समझौता ज्ञापन के अनुसार एस०टी०सी० के कार्य-निष्पादन की समीक्षा अर्द्ध-वार्षिक आधार पर की जाती है।

(च) स्थायी संसदीय समिति की सिफारिशें एस०टी०सी० और एमएमटीसी का विलय करने और विदेश में इन दोनों संगठनों द्वारा एक की कार्यालय में हिस्सेदारी करने के बारे में थीं। संसदीय समिति के विचारार्थ कृत कार्रवाई का एक उत्तर 23 फरवरी, 1996 को पहले ही राज्य सभा सचिवालय को भेजा जा चुका है।

Per Capita Income in Super Bazar

1112. SHRI GOVINDRAM MIRI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether per capita income in the Super Bazar has increased or decreased in 1994-95 as compared to 1992-93 and 1993-94;

(b) if so, the per capita income in the Super Bazar in 1992-93, 1993-94 and 1994-95; and

(c) the estimated per capita income in the Super Bazar during the first three months of the current financial year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPTT. OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI VENOD SHARMA): (a) It has been reported by the Super Bazar that the per capita income has increased during the year 1994-95 compared to 1992-93 and 1993-94.

(b) The per capita income during the last three years furnished by Super Bazar is as follows: